

न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)**पीठासीन अधिकारी - अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 005/2022(नि.पं.) (GCMS 2022/52)	दायर दिनांक 31.03.2022	निर्णय दिनांक 15.06.2022
---	---------------------------	-----------------------------

अनवान

ग्राम पंचायत बस्सी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बस्सी पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़।

निगराकार**बनाम**

श्रीमती निर्मला कंवर पत्नी भारत सिंह चुण्डावत उम्र बालिग निवासी बस्सी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ हाल निवासी C/O विजय सिंह राठौड़, प्लॉट नंबर 270 गली नंबर 07 शिक्षक कॉलोनी चौपासनी जोधपुर 342008।

गैर निगराकार

उपस्थिति :- ललित लड़ा
अनुपस्थित

अधिवक्ता निगराकार
गैर-निगराकार

धनगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा जारी पट्टा संख्या 47 पुस्तक संख्या 424 दिनांक 28.10.2016 को निरस्त कराने बाबत

--: निर्णय :-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगराकार ने एक निगरानी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरुद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैर निगराकार को पुराने आवासीय गृह का विनियमितिकरण का पट्टा विलेख संख्या 047 दिनांक 28.10.2016को पंचायती राज अधिनियम 1994, पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के अन्तर्गत प्रारूप 23 'क' जारी किया गया जिसके संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर जांच समिति द्वारा जांच किए जाने पर पट्टा सं. 047 गैर निगराकार को न्याय नियम एवं मौका स्थिति के विपरीत जारी किये जाने की जानकारी होने से पट्टा निरस्त कराए जाने हेतु यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। पट्टा संख्या 47 दिनांक 28.10.2016 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों के विपरित जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। गैर निगराकार को जो पट्टा जारी किया गया है वह पुश्तैनी आवास ग्राम बस्सी में अवस्थित का जारी किया गया है। गैर निगराकार श्रीमती निर्मला कंवर का पुश्तैनी मकान का दिनांक 15.02.2022 को जांच समिति द्वारा पर्चा मौका बनाया गया। मौका स्थिति अनुसार 2397.56 वर्ग फीट भूमि पर ही पुश्तैनी आवास निर्मित है। जबकि पट्टा तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा 3159 वर्गफीट का जारी किया गया है। इस प्रकार गैर निगराकार को 761.44 वर्गफीट का पट्टा नियम 157 (1) के तहत गलत जारी किया

गया है। नियम 157 (1) में जहां व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हो, उनका पट्टा विनियमितकरण का जारी किया जाता है। गैर निगराकार का पुश्तैनी मकान 2397.56 वर्गफीट पर ही निर्मित होकर 2397.56 वर्गफीट पर ही कब्जा है। इसके बाद भी 761.44 वर्गफीट का पट्टा अधिक जारी किया गया है जो गलत है। गैर निगराकार को दिनांक 28.10.2016 को जो पट्टा जारी किया गया है उसमें शिवराज सिंह पिता रघुवीर सिंह के आवासीय परिसर के पश्चिम भाग का 5 फीट हिस्सा एवं गैर निगराकार के मकान के बाहर आम रास्ते पर चबुतरा भी सम्मिलित है जो कि नियमानुसार गलत है। श्रीमती निर्मला कंवर गैर निगराकार ने पुराने गृहों का विनियमितकरण बाबत पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ पड़ोस पूर्व दिशा में स्वयं का मकान दर्शाया है व पट्टा संख्या 47 में भी पूर्व दिशा में स्वयं का मकान दर्शा रखा है जबकि मौका स्थिति के अनुसार पूर्व दिशा में शिवराज सिंह व गंगा सिंह का आवासीय परिसर स्थित है। गैर निगराकार को जो पट्टा जारी किया गया है मौके की स्थिति के अनुसार सही नहीं है। शिवराज सिंह का आवासीय परिसर एवं चबुतरे का नाप भी पुश्तैनी पट्टे में सम्मिलित कर लिया गया है जो कि मौका स्थिति एवं गैर निगराकार/विपक्षी के कब्जे के अनुसार सही जारी नहीं किया गया है। जिससे निरस्त किए जाने योग्य है। श्रीमती निर्मला कंवर ने मौके की सही स्थिति एवं पड़ोस अंकित नहीं कर पट्टा विलेख प्राप्त किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। पट्टा विलेख में जो पड़ोस अंकित किए गए हैं वह निम्न है - पूर्व :- स्वयं का मकान, पश्चिम :- सुरेन्द्रसिंह का मकान, उत्तर :- सुरेन्द्र सिंह का मकान एवं दक्षिण :- आम रास्ता अंकित किये गये है। विपक्षी ने पट्टा प्राप्त करने हेतु उपरोक्तानुसार ही पड़ोस बताए है जबकि मौके पर पड़ोस निम्न है - पूर्व :- गंगा सिंह व शिवराज सिंह का आवासीय परिसर, पश्चिम :- सुरेन्द्र सिंह का मकान, उत्तर :- सुरेन्द्रसिंह का मकान एवं दक्षिण :- आम रास्ता व चबुतरा इस प्रकार मौका स्थिति के अनुसार उपरोक्त मकान का कुल क्षेत्रफल 2397.56 वर्गफीट है जबकि विपक्षी को जारी पट्टे का क्षेत्रफल 3159 वर्गफीट है जिसमें मकान के साथ आम रास्ते पर बने हुए चबुतरे का एवं पूर्व दिशा में शिवराज सिंह के आवासीय परिसर का भाग भी सम्मिलित है। जिससे विपक्षी को जारी पट्टा संख्या 47 मौके की स्थिति, पुराना कब्जा, न्याय एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। निगरानी उपर वर्णित कारणों से स्वीकार फरमायी जाकर विपक्षी के नाम जारी पट्टा निरस्त किए जाने हेतु जांच रिपोर्ट के आधार पर पूर्ण न्याय शुल्क पर वास्ते कार्यवाही पेश की जा रही है। धारा 97 पंचायत राज अधिनियम के तहत विपक्षी को पट्टा जारी किया गया उसके औचित्य एवं वैधानिकता की विस्तृत जांच करते हुए पट्टा निरस्तगी का अधिकार श्रीमान् को प्रदत्त किए जाने से यह निगरानी श्रीमान् के श्रवणाधिकार की होकर वास्ते कार्यवाही पेश है। पट्टा निरस्त कराए जाने हेतु निगरानी की कोई कानूनी मयाद नहीं है। फिर भी दिनांक 15.02.2022 को जांच रिपोर्ट में उक्त पट्टा विलेख विधि विरुद्ध जारी होने की जानकारी होते ही अन्दर अवधि 90 दिन बिना किसी देरी के निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रार्थना है कि निगरानी पंचायत स्वीकार फरमायी जाकर विपक्षी को जारी पट्टा विलेख संख्या 47 दिनांक 28.10.2016 मौके की स्थिति न्याय एवं नियमों के विपरीत होने से विपरीत। निरस्त फरमाया जावे।

इस पर निगरानी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारान को जरिये नोटिस के तलब किया गया एवं अधीनस्थ

ग्राम पंचायत बस्सी से मूल अभिलेख तलब किया गया। इस पर दिनांक 13.04.2022 को विकास अधिकारी पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/पंसचि/पंचायत/2022-23/17 दिनांक 13.04.2022 से मूल अभिलेख प्रेषित किया गया जो कि पत्रावली के हम किता होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 07.06.2022 को गैर निगराकारान के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से गैर निगराकारान की अनुपस्थिति रिकार्ड की गई।

दिनांक 15.06.2022 को अधिवक्ता निगराकार हाजिर आये एवं प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। इस पर हाजिर अधिवक्ता निगराकार द्वारा की गई बहस पत्रावली को एक तरफा सुना गया। विद्वान अधिवक्ता निगराकार द्वारा निगरानी मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि गैरनिगराकार को पुराने आवासीय गृह का विनियमितिकरण का पट्टा विलेख संख्या 047 दिनांक 28.10.2016 को पंचायती राज अधिनियम 1994, पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के अन्तर्गत प्रारूप 23 'क' जारी किया गया जिसके संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर जांच समिति द्वारा जांच किए जाने पर पट्टा सं. 047 गैर-निगराकार को न्याय नियम एवं मौका स्थिति के विपरीत जारी किये जाने की जानकारी होने से पट्टा निरस्त कराए जाने हेतु यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। गैरनिगराकार को जो पट्टा जारी किया गया है वह पुश्तैनी आवास ग्राम बस्सी में अवस्थित का जारी किया गया है। गैर निगराकार का पुश्तैनी मकान का दिनांक 15.02.2022 को जांच समिति द्वारा पर्चा मौका बनाया गया। मौका स्थिति अनुसार 2397.56 वर्ग फीट भूमि पर ही पुश्तैनी आवास निर्मित है। जबकि पट्टा तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा 3159 वर्गफीट का जारी किया गया है। इस प्रकार गैर निगराकार को 761.44 वर्गफीट का पट्टा नियम 157 (1) के तहत गलत जारी किया गया है। नियम 157 (1) में जहां व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हो, उनका पट्टा विनियमितिकरण का जारी किया जाता है। गैर निगराकार का पुश्तैनी मकान 2397.56 वर्गफीट पर ही निर्मित होकर 2397.56 वर्गफीट पर ही कब्जा है। इसके बाद भी 761.44 वर्गफीट का पट्टा अधिक जारी किया गया है जो गलत है। गैर निगराकार को दिनांक 28.10.2016 को जो पट्टा जारी किया गया है उसमें शिवराज सिंह पिता रघुवीर सिंह के आवासीय परिसर के पश्चिम भाग का 5 फीट हिस्सा एवं गैर निगराकार के मकान के बाहर आम रास्ते पर चबुतरा भी सम्मिलित है जो कि नियमानुसार गलत है। श्रीमती निर्मला कंवर गैर निगराकार ने पुराने गृहों का विनियमितिकरण बाबत पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ पड़ोस पूर्व दिशा में स्वयं का मकान दर्शाया है व पट्टा संख्या 47 में भी पूर्व दिशा में स्वयं का मकान दर्शा रखा है जबकि मौका स्थिति के अनुसार पूर्व दिशा में शिवराज सिंह व गंगा सिंह का आवासीय परिसर स्थित है। गैर निगराकार को जो पट्टा जारी किया गया है मौके की स्थिति के अनुसार सही नहीं है। शिवराज सिंह का आवासीय परिसर एवं चबुतरे का नाप भी पुश्तैनी पट्टे में सम्मिलित कर लिया गया है जो कि मौका स्थिति एवं गैर निगराकार/विपक्षी के कब्जे के अनुसार सही जारी नहीं किया गया है। जिससे निरस्त किए जाने योग्य है। श्रीमती निर्मला कंवर ने मौके की सही स्थिति एवं पड़ोस अंकित नहीं कर पट्टा विलेख प्राप्त किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। मौका स्थिति के अनुसार मकान का कुल क्षेत्रफल 2397.56 वर्गफीट है जबकि विपक्षी को जारी पट्टे का क्षेत्रफल 3159 वर्गफीट है जिसमें मकान के साथ आम रास्ते

पर बने हुए चबुतरे का एवं पूर्व दिशा में शिवराज सिंह के आवासीय परिसर का भाग भी सम्मिलित है। जिससे विपक्षी को जारी पट्टा संख्या 47 मौके की स्थिति, पुराना कब्जा, न्याय एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। इसी प्रार्थना के साथ विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का परिशीलन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। प्रकरण में तथ्यों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। हमने विधि का अवलोकन किया पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 का गहनता पूर्वक परिशीलन किया।

97. Power of revision and review by Government.- (1) The State Government may, either of its own motion or on an application from any person interested, call for and examine the record of a Panchayati Raj Institution or of a Standing Committee or Sub-Committee thereof in respect of any proceedings to satisfy itself as to the correctness, legality or propriety of any decision or order passed therein or as to the regularity of such proceedings and, if in any case, it appears to the State Government that any such decision or order be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, it may pass order accordingly:

Provided that the State Government shall not pass any order prejudicial to any party unless such party has a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(2) The State Government may stay the execution of any such decision or order prejudicial to any party, pending the exercise of its powers under sub-section (1) in respect thereof.

(3) The State Government may, of its own motion or on an application received from any person interested, at any time within ninety days of the passing of an order under Subsec.

(1), review any such order if it was passed by it under any mistake, whether of fact or of law or in ignorance of any material fact. The provisions contained in the proviso to Sub-sec. (1) and in Sec. (2) shall apply to a proceeding under this sub-section.

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अनुसार राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्हीं भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता, औचित्य एवं नियमित होने की दृष्टि से अभिलेख मंगाने, परीक्षण करने एवं ऐसे आदेश/निर्णय/कार्यवाही प्रस्ताव को संशोधित करने, उलट दिये जाने, उपांतरित किये जाने या पुनः विचारार्थ प्रतिप्रेषित किये जाने की अधिकारिता रखती है। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ4(10)परावि/विधि/संशोधन/2004/3690 दिनांक 13.12.2004 के अनुसार उक्त धारा 97 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन जिला कलक्टर को पुनर्स्थापित कर दिया गया है। निगराकार द्वारा हस्तगत निगरानी में विवादित पट्टे के संबंध में उसकी विधिकता/औचित्य के संबंध में प्रश्न उठाया गया है, ऐसी स्थिति में प्रकरण इस न्यायालय में पोषणीय पाया जाता है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख की अवलोकन/परिशीलन किया। पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 9 में

आबादी भूमि के संबंध में प्रक्रियात्मक प्रावधान किये गये हैं। उक्त प्रावधानों के अनुसार नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये हैं। पंचायतीराज नियम, 1966 के नियम 157 में निम्नानुसार प्रावधान प्रावधित किये गये हैं।

157. Regularisation of old houses.-

[1][Where the persons are in possession of the old houses in Abadi land and desire to get a patta issued, patta may be issued by the Panchayat in Form XXIII-A after depositing the charges as under : -

- | | |
|---|------------|
| (a) For old houses constructed more than fifty years before the date of commencement of these rules | Rs. 100 /- |
| (b) For old houses constructed [during the seventy years immediately preceding to date of 31st December, 2016]. | Rs. 200/- |

[2][Provided that no fees shall be charged under sub-clause (a) an only 10 percent fees shall be charged under sub-clause (b) of clause (i) above from the families included in the list of below poverty line.]

हमने अधीनस्थ ग्राम पंचायत बस्सी से प्राप्त अभिलेख का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में पुराने गृहों को विनियमितीकरण के संबंध में प्रावधान प्रावधित किये गये हैं। प्रावधानुसार जहाँ व्यक्तियों के कब्जे से आबादी भूमि में पुराने गृहों हो और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो तो वह नियमानुसार राशि कराये जाने के पश्चात् पंचायत द्वारा पट्टे जारी किया जा सकेगा। यहाँ यह तथ्य महत्वपूर्ण के है कि ग्राम पंचायत को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में आबादी भूमि में स्थित पुराने गृहों विनियमितकरण के संबंध में प्रावधान प्रावधित किये गये हैं। उक्त प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायत को केवल मात्र आबादी भूमि स्थित गृहों के विनियमितीकरण किये जाने की ही क्षेत्राधिकारिता है गैर आबादी भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत को अधिकार राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 द्वारा प्रदान नहीं किये गये हैं।

हमने अधीनस्थ ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत अभिलेख में पत्रालवी में संलग्न आज्ञाओं की सूची में वर्णित आज्ञाओं में आज्ञा संख्या 2 दिनांक 28.06.2016 से प्रार्थीया को पुश्तैनी मकान के मौका निरीक्षण हेतु 3 वार्ड पंचों की नियुक्ति की गई है। आज्ञा संख्या 3 दिनांक 05.07.2016 से 3 वार्ड पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जाकर मौका निरीक्षण दिनांक 28.06.2016 से किया जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उक्त निरीक्षण रिपोर्ट पंचगण के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त रिपोर्ट पर वार्ड पंच प्रीति वर्मा के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। प्रकरण में यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि मौका निरीक्षण पूर्ण कोरम से नहीं किया गया है। इसके साथ ही रिपोर्ट पर वार्ड पंच द्वारा मौका निरीक्षण दिनांक 28.06.2016 को किया जाना अंकित किया गया है जबकि पत्र जारी किये जाने की दिनांक 25.06.2016 अंकित है। आवेदक के प्रार्थना पत्र में भूखण्ड का किसी भी प्रकार से नाप-चौक क्षेत्रफल इत्यादि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाकर प्रार्थना पत्र में अंकन नहीं है। भूखण्ड के संबंध में पटवारी रिपोर्ट/किस्म भूमि प्रमाण-पत्र नहीं है। ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा जारी सूचना पत्र बाबत् आबादी भूमि में स्थित पुराने गृह के

विनियमितीकरण के संबंध में आक्षेप आमंत्रित किये जाने वाले प्रारूप में एवं ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा जारी विवादित पट्टा संख्या 47 के नाप-चौक की भिन्नता है। जहाँ आक्षेप आमंत्रित पत्र में 71 फीट का अंकन किया गया है जबकि ग्राम पंचायत 74 फीट का पट्टा जारी किया गया है। इसके साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा के अवलोकन से जाहिर होता है कि पूर्व दिशा में शिवराज सिंह का मकान स्थित है जबकि आवेदन पत्र में स्वयं का मकान अंकित किया गया है। वार्ड पंचों की कमेटी रिपोर्ट में भूखण्ड के मौका नक्शा प्रस्तुत किया गया है उस पर एक मात्र एक वार्ड पंच के हस्ताक्षर अंकित है। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में पुराने गृहों को विनियमितकरण किये जाने के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य बने हुये मकान का मौका नक्शा ही है एवं पत्रावली पर उपलब्ध अतिरिक्त विकास अधिकारी एवं 2 सहायक विकास अधिकारी की संयुक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 15.02.2022 के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा आवासीय पुश्तैनी पट्टा संख्या 47 दिनांक 28.10.2016 के मकान की वस्तु-स्थिति जिसमें मकान का नक्शा को रिकार्ड पर लिये बिना है विवादित पट्टा जारी किया जाना जाहिर होता है, ऐसी स्थिति में गैर निगराकार को निगराधीन पट्टा संख्या 47 में कुल 3159 वर्गफीट का पट्टा किस प्रकार जारी किया गया है। इसका अंकन पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से स्पष्ट नहीं होता है, ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट होता है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में पुराने गृहों को विनियमितकरण के संबंध में प्रावधानों की पूर्ण रूप से अवहेलना किया जाना जाहिर होता है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर उक्त विवादित पट्टा जारी किया जाना जाहिर होता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत बस्सी पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत पुराने गृहों के विनियमितकरण के प्रावधानों के तहत आवेदक को पट्टा जारी किये जाने में विधिक भूल की जाकर पट्टा जारी किये जाने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा त्रुटि कारित की गई है। पंचायतीराज अधिनियम की धारा 97 के तहत पंचायतीराज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता के परीक्षण का ही प्रावधान है, ऐसी स्थिति में विवादित बुक संख्या 424 पट्टा संख्या 047 दिनांक 28.10.2016 को खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर निगराकार द्वारा उठाये गये ग्राम पंचायत बस्सी पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ द्वारा विवादित बुक संख्या 424 पट्टा संख्या 047 दिनांक 28.10.2016 के संबंध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत के अभिलेख के गहनता पूर्वक परीक्षण करने पर न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत पुराने गृहों के विनियमितीकरण के प्रावधानों के तहत आवेदक को पट्टा जारी किये जाने में विधिक भूल की जाकर पट्टा जारी किये जाने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा त्रुटि कारित किया जाना प्रकट होता है, ऐसी स्थिति में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किया जाता है, एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा जारी बुक संख्या 424 पट्टा संख्या 047 दिनांक 28.10.2016 जो कि गैर निगराकार श्रीमती निर्मला कंवर पत्नी भारत सिंह चुण्डावत उम्र बालिग निवासी बस्सी तहसील

बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ के पक्ष में जारी किया गया है को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है, चूंकि अधीनस्थ ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा उक्त विवादित पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में पुराने गृहों को विनियमितकरण के तहत जारी किया गया है ऐसी स्थिति में गैर-निगराकार श्रीमती निर्मला कंवर पत्नी भारत सिंह चुण्डावत उम्र बालिग निवासी बस्सी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ हाल निवासी C/O विजय सिंह राठौड़, प्लॉट नंबर 270 गली नंबर 07 शिक्षक कॉलोनी चौपासनी जोधपुर 342008 अपने हक हिस्से कब्जे अनुसार नवीन पट्टा जारी करवाने की कार्यवाही किये जाने बाबत् स्वतंत्र है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी चित्तौड़गढ़ को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 15.06.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पौसवाल)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़